

(ब) यदि हां, तो यह समाचार कहां तक सच है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) इस समाचार की ओर मंत्रालय का ध्यान दिलाया गया है।

(ख) समाचार में छपी बातें वास्तव में सही हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना 618 (आपरेशन फण्ड) के लिए मूल स्वीकृत परिष्वय 95.40 करोड़ रुपए था जो विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा वल वस्तुओं के विक्रय से सृजित राशि पर आधारित होता है। 11-1-1974 से विश्व खाद्य कार्यक्रम की वस्तुओं के स्थानान्तरण मूल्य में संशोधन होने पर परियोजना के प्रावधान को संशोधित करके 116.40 करोड़ रुपए दिया गया है। भारत सरकार और विश्व खाद्य कार्यक्रम प्राधिकारियों के बीच संचालन-योजना (प्लान आफ आपरेशन) के आधार पर परियोजना को भारतीय डेरी निगम क्रियावित्त करता रहा है। भारतीय डेरी निगम सरकार को वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है और प्रति-वर्ष सनदी लेखाकारों की एक फर्म द्वारा उसके लेखा की लेखा-परीक्षा भी की जाती है।

पोरबंदर और जूनागढ़ (गुजरात) में
घाउटडोर स्टेडियमों के लिए सहायता

* 182. श्री धर्मसिंह भाई पटेल :
क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने पोरबंदर और जूनागढ़ शहरों में घाउटडोर स्टेडियमों के लिए योजनाएं और प्राक्कलन केन्द्रीय सरकार को भेजे हैं और यदि हां, तो प्रत्येक का प्राक्कलन क्या है ;

(ख) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है ;
और

(ग) पोरबंदर और जूनागढ़ में घाउटडोर स्टेडियम बनाने की मजूरी और सहायता कब दी जायेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) जी, हां यद्यपि राज्य सरकारों को सकेत दिए गए थे कि सीमित निधियों को ध्यान में रखते हुए नये प्रस्तावों पर विचार करना सम्भव नहीं होगा तो भी पोरबंदर तथा जूनागढ़ स्टेडियमों के अनुमान सितम्बर, 1977 के अंत में प्राप्त हुए। ये अनुमान क्रमशः 2,69,805 ₹० और 2,60,500 ₹० के हैं। निधियों की कमी के कारण इन पर वित्तीय वर्ष 1978-79 में विचार किया जायगा।

Subsidies to Fishermen of Goa, Daman and Diu

1564. SHRI AMRUT KASAR Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the fishermen of the Union Territory of Goa, Daman and Diu were given subsidies for purchasing the engines of fishing vessels;

(b) whether the same subsidies have been stopped; and

(c) if so, the reasons thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA). (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir, but the subsidy has been reduced from 40 per cent to 5 per cent.

(c) During the fourth five year plan period, the Government approved 50

per cent loan and 40 per cent subsidy in respect of indigenous engines. But on reviewing the situation of mechanisation programme during the fifth plan of the Government of Goa it was seen that in view of the subsidy element there was a scope for malpractices and therefore the State Government proposed to reduce the subsidy from 40 per cent to 5 per cent and to increase the quantum of loan from 50 per cent to 75 per cent. The remaining 20 per cent was kept as individuals contribution. The above proposal was agreed to by the Government of India and now the subsidy given to fishermen for marine engines for fishing boats is 5 per cent with a loan component of 75 per cent.

Withdrawal from the Membership of the Delhi School Teachers' Co-operative House Building Society

1565 SHRI T. S. NAGI Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state

(a) the number of persons who have withdrawn their names from the membership of the Delhi School Teachers' Co-operative House Building Society, Delhi and have taken refund from the so-called Managing Committee which got elected during Emergency

(b) the total number of teacher and non-teacher members of the Society separately and year wise according to their year of enrolment and

(c) the total number of persons who filed affidavits with the office of the Registrar, Coop Societies, Delhi in August/September 1977 claiming membership of the Society and the action taken by the Registrar's Office so far to accept their membership?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND

REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT) (a) The Society has reported that 340 persons have taken refund of their amount at their own request.

(b) The information is being collected.

(c) 283 affidavits were received up to 16th August 1977 which was the due date. Of these 2 did not relate to this society. The effective number thus was 281. All the affidavits were examined by a committee constituted by the I.T. Governor, Delhi. The report of the Committee has been sent to the Managing Committee for further necessary action. In addition 37 objections were received after the due date and these were sent to the Managing Committee of the Society for necessary action as desired by it.

टाइप IV फ वार्डर के प्लान्टियो से मार्केट रेट बिगा जाना

1566 श्री नवाब गिह चोहान क्या निर्माण और आवास तथा पर्यटन और पुनर्वास मंत्री यह जानने की कृपा करेंगे कि

(क) दिल्ली में टाइप IV में रहने वाले निम्न निम्न व्यक्तियों का मार्केट रेट लिया जा रहा है,

(ग) उसके क्या कारण हैं और किन मतानों के लिये लिया जा रहा है

(ग) क्या जिन व्यक्तियों ने मार्केट रेट लिया जा रहा है वे अब भी मीवा में हैं और

(घ) क्या सरकार कुछ आवेदन पत्रों पर भी कोई कार्यवाही कर रही है जिससे संबंधित व्यक्तियों को कुछ राहत मिल सके?